डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2015-17

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 61 ● अंक 05 ● भोपाल ● 1-15 अगस्त, 2017 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

मध्यप्रदेश करेगा दूसरी कृषि क्रांति- मुख्यमंत्री श्री चौहान

प्याज खरीदी और नीलामी में गड़बड़ी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश अब दूसरी कृषि क्रांति करेगा। इसके माध्यम से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलेगा और उनकी समस्या का स्थायी समाधान होगा। देश को भी नई दिशा मिलेगी। यहां मंत्रालय में प्याज खरीदी की समीक्षा करते हुये मुख्यमंत्री ने प्याज खरीदी और नीलामी की मानिटरिंग के लिये उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिये। श्री चौहान ने कहा कि प्याज खरीदी, बिक्री और नीलामी की प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।

श्री चौहान ने कहा कि प्याज खरीदी और नीलामी की पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। उच्चस्तरीय निगरानी समिति अगले तीन महीने तक इस व्यवस्था के संचालन की निगरानी करेगी। उन्होंने कहा कि प्याज खरीदी की जांच भी की जायेगी। इसके लिये जिन केन्द्रों से शिकायत मिलेगी, वहां विशेष जांच दल भेजकर जांच करायी जायेगी।

बैठक में बताया गया कि अब तक 8लाख 76हजार मीट्रिक टन प्याज की खरीदी की जा चुकी है। इसमें से करीब 90 प्रतिशत प्याज की नीलामी की जा चुकी है। भारत सरकार ने प्याज की खरीदी की मात्रा को देखते हुये 20 प्रतिशत प्याज खराब होने के संभावना जातायी थी जबकि अभी केवल 5 प्रतिशत प्याज खराब हुआ है। राशन दुकानों से गरीबों को प्याज उपलब्ध कराने की सुचारु व्यवस्था अत्याधिक सफल रही है। जल्दी ही प्याज के शेष स्टॉक का निराकरण किया जायेगा। प्याज खरीदी के माध्यम से 1 लाख 54 हजार किसान लाभान्वित हुये हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि खरीदी और नीलामी की प्रक्रिया की जांच करते समय किसानों को भुगतान की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होना चाहिये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्याज खरीदी और नीलामी से जुड़ा जो सरकारी अमला सरकार की मंशा और तय प्रक्रिया के अनुरूप कार्य कर रहा है, उन्हें पूरा संरक्षण दिया जायेगा। अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में बताया गया कि प्याज खरीदी की व्यवस्था से प्याज उत्पादक किसान पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्हें अपनी उपज का लाभकारी मूल्य मिल गया है। पूरी व्यवस्था सुचारू रुप से संचालित है। श्री चौहान ने कृषि लागत मूल्य निर्धारण आयोग की जल्दी स्थापना कर कार्य शुरू करने के निर्देश दिये।

बैठक में कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी.मीणा, प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जैविक बीज उत्पादन के लिए 8 शासकीय प्रक्षेत्र का चयन

भोपाल। प्रदेश में जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया और जैविक बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 8 शासकीय प्रक्षेत्रों का पूर्ण रूप से जैविक बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिये चयन किया गया है। इन प्रक्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का रकबा करीब 251 हेक्टेयर चयनित प्रक्षेत्र है। चयनित प्रक्षेत्रों में डिण्डोरी, सिवनी जिले का भोमाकटिया, छिन्दवाड़ा जिले का देलाखारी, बालाघाट जिले का गढ़ी, देवास जिले का चन्द्रकेशर, ग्वालियर का महुआखेड़ा, अलीराजपुर का जोबट और बैतूल जिले का गुदगांव शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में जैविक कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना का कार्य भी प्रगति पर है।

प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये मध्यप्रदेश जैविक नीति 11 मई 2011 से लागू की गई है। इसके बाद 3 मार्च 2014 को जैविक खेती विकास परिषद का गठन किया गया। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के उददेश्य से 12वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012-13 में प्रारंभ की गई। इसमें प्रदेश के 16जिलों अलीराजपुर, झाबुआ, बैतूल, खंडवा, सागर, दमोह, छिन्दवाड़ा, मंडला, बालाघाट, उमरिया, डिण्डोरी, कटनी, अनूपपुर, श्योपुर कलां, भोपाल और सीहोर के 32 विकासखंडों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में योजना भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश पर 5 जिलों के 5 विकासखंडों में योजना संचालित की गई। इसके बाद इसका विस्तार करते हुए इसे 7 जिलों के 7 और विकासखंडों में लागू किया गया। एनजीटी के निर्देशानुसार जैविक खेती विकास कार्यक्रम नर्मदा नदी के किनारों पर प्रमुख रूप से लागू किया गया है। प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में जैविक उत्पाद के विपणन के लिये अलग से प्लेटफार्म बनाये गये हैं।

जीएसटी लागू के बाद रासायनिक उर्वरकों के मूल्य में कमी

भोपाल। प्रदेश में एक जुलाई, 2017 से वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू होने के बाद रासायनिक उर्वरकों के मूल्यों में कमी आई है। रासायनिक उर्वरक डीएपी 10 रूपये 75 पैसे, यूरिया 6 रूपये, एनपीके 12:32:16 रूपये 20, एनपीके 10:26:26 पाँच रूपये, एमओपी 5 रूपये 38पैसे और सिंगल बोरी फास्फेट के प्रति बोरी मूल्य पर 5 रूपये 14 पैसे की कमी आई है। सहकारी समिति और विपणन संघ को जीएसटी लागू होने के बाद रासायनिक उर्वरकों में कम हुई दरों पर किसानों को बिक्री किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

किसानो से बहुफसली खेती करने की अपील

होशंगाबाद। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानो से बहुफसली खेती को अपनाने की अपील की है। उन्होने कहा कि सभी किसान खरीफ तथा रबी के मौसम मे एक ही फसल बहुत अधिक क्षेत्रफल मे न बोएं। उसके स्थान पर एक से अधिक फसलें लगाये। इससे किसी एक फसल का उत्पादन एक साथ नही बढेगा तथा फसल उत्पाद की कीमत को स्थिर रखने मे सहायता मिलेगी। यदि कई फसलों मे से कोई एक फसल खराब भी होती है तो अन्य फसलो से किसान को कुछ न कुछ उपज अवश्य मिलेगी।

मण्डारण क्षमता और प्रोसेसिंग इकाईयाँ बढ़ायी जायेंगी - श्री चौहान

एग्रीकल्चर टास्क फोर्स की बैठक में कृषि विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के उपाय किये जायेंगे। तात्कालिक उपाय में किसानों को राहत पहुँचाने का काम जारी रहेगा। दीर्घकालिक उपाय में भण्डारण क्षमता बढ़ाई जायेगी, अधिकतम प्रोसेसिंग इकाईयाँ लगायी जायेंगी, मूल्य संवर्धन किया जायेगा और ग्लोबल मार्केट का लाभ लिया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान यहाँ मंत्रालय में एग्रीकल्चर टास्क फोर्स की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में कृषि विशेषज्ञों के साथ किसानों को अधिक उत्पादन के बाद भी उचित मूल्य नहीं मिलने की चुनौती पर विचार विमर्श किया गया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कृषि उत्पादन वृद्धि में कीर्तिमान बना है। पर इसके साथ किसानों की उपज का मूल्य गिरने की समस्या सामने आई है। इसके समाधान की आदर्श व्यवस्था की जायेगी। इसके अंतर्गत ऐसी नीति बनाई जायेगी जिसमें कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन और प्रोसेसिंग की व्यवस्था रहेगी। इसमें प्रोसेसिंग इकाईयों और भण्डारण क्षमता के लिये अधोसंरचना बनाने के लिये किसानों के युवा बच्चों को प्रोत्साहित किया जायेगा। प्रदेश में प्याज, आलू, फल-सब्जियों के लिये कोल्ड स्टोरेज श्रंखला बनायी जायेगी। इसके साथ ही मार्केटिंग पर ध्यान दिया जायेगा। प्रदेश के विशिष्ट उत्पादों जैसे मालवा के आलू, शरबती गेहूँ, नर्मदा किनारे के क्षेत्र में उत्पादित होने वाली तुअर दाल, नीमच के जीरन में पैदा होने वाली एक कली की लहसुन की मार्केटिंग की जायेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में पिछले पाँच सालों में खाद्यान्न का उत्पादन दोगुना हो गया है। प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ा है। बीज प्रतिस्थापन की दर 30 प्रतिशत हो गयी है। खाद के अग्रिम भण्डारण की व्यवस्था की गई है। मिट्टी परीक्षण में प्रदेश देश में अग्रणी है। उत्पादन बढ़ाने के सभी पक्षों पर तेजी से काम किया गया है जिससे उत्पादन बढ़ा है। उत्पादन बढ़ने के बाद भी किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलने की समस्या सामने आई है। इसके लिये तात्कालिक रूप से प्याज आठ रूपये प्रति किलो तथा तुअर, उड़द, मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई है। इसके बाद भी समस्या के समाधान के लिये दीर्घकालिक उपाय आवश्यक है।

बैठक में उपस्थित कृषि विशेषज्ञों और मंत्रियों ने किसानों को उपज का उचित मिले, इसके लिये सुझाव दिये।

कृषि विशेषज्ञ डॉ. अशोक गुलाटी - कृषि उत्पादों के लिये भण्डारण क्षमता 5 से 10 गुना बढ़ायी जाये। इसके लिये निवेश किया जाये। कृषि उत्पादों की मार्केटिंग के लिये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से लिंकेज किया जाये। गुजरात में दुग्ध उत्पादन के लिये चलाये गये ऑपरेशन फ्लड की तरह मध्यप्रदेश में सब्जी उत्पादन के लिये ऑपरेशन वेजीस चलाया जाये।

कृषि विशेषज्ञ डॉ. पंजाब सिंह - मध्यप्रदेश की समस्या को चुनौती के रूप में लें। फूड प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन में निवेश के माध्मय से ग्रामीण युवाओं को रोजगार दें। कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ उसकी सुरक्षा के उपायों पर ध्यान दें।

कृषि क्षेत्र के इंटरप्रेन्योर श्री प्रशांत अग्रवाल- भण्डारण और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में युवाओं के प्रशिक्षण पर ध्यान दें। प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला स्तर पर हो। ग्राम स्तर पर सब्जी मंडियों में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो।

कृषि विशेषज्ञ डॉ. ज्ञानेन्द्र सिंह- कृषि यंत्रों के कस्टम हायरिंग के तरह भण्डारण और प्रोसेसिंग में भी व्यवस्था की जाये। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उत्पादों के प्रोसेसिंग और भण्डारण के लिये अधोसरंचना विकसित की जाये।

कृषि विशेषज्ञ डॉ. आर.के. पाटिल- गाँव - गाँव में प्रोसेसिंग की छोटी इकाईयाँ स्थापित की जायें। प्रोसेस्ड फूड के लिये उत्पाद तैयार किये जायें।

वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया - किसानों के लिये समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित की जाये। भण्डारण क्षमता बढ़ाई जाये।

कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन - क्वालिटी फूड पर ध्यान देना चाहिये। जैविक उत्पादों के लिये बेहतर अवसर हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव - भण्डारण क्षमता के लिये राष्ट्रीय संस्थान व्यवस्था करे। किसान कृषि उत्पादों के मूल्यों के उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं हों, ऐसी व्यवस्था की जाये।

वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार - प्याज और टमाटर जैसे उत्पादों की प्रोसेसिंग इकाई जिलों में स्थापित हो।

ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन - वैश्विक बाजार में निर्यात किये जाने योग्य उत्पाद तैयार करने के संयंत्र स्थापित किये जायें।

सहकारिता राज्यमंत्री श्री विश्वास सारंग- सहकारिता के क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग इकाईयाँ लगायी जायें। भण्डारण के लिये मल्टी यूटीलिटी गोदाम बनाये जायें।

बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे, नर्मदा घाटी विकास राज्यमंत्री श्री लाल सिंह आर्य, पर्यटन राज्यमंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा, उद्यानिकी राज्यमंत्री श्री सूर्यप्रकाश मीणा, मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

पीडीएस के 31 लाख परिवारों को 2 रु. किलो की दर पर एक लाख टन प्याज वितरित

कमजोर वर्ग के परिवारों ने जाहिर की प्रसन्नता

भोपाल। अमराई बस्ती बागसेवनिया भोपाल के श्री दादा राव 2 रुपये किलो की दर पर पर प्याज खरीदने वाले प्रदेश के 31 लाख लोगों में से एक हैं। पाँच सदस्यीय परिवार के मुखिया श्री राव बताते है कि खरीदी गई 50 किलो प्याज अगले 6माह की उनके परिवार की जरूरत को पूरा करेगी। मजदूरी से अपने परिवार की आजीविका चलाने वाले 55 वर्षीय श्री दादा राव राशन की दुकान से मिली प्याज को बाजार में मिलने वाली प्याज के समान गुणवत्ता की मानते हैं। उन्होंने बताया कि सप्ताह में 1 से 3 किलो प्याज उन्हें लेना पड़ती थी। बाजार में 10 से 15 रुपये प्रति किलो की दर होने से वह एक दो किलो ही खरीदते थे। राशन दुकान से नाम मात्र की कीमत 2 रुपये प्रति किलो होने से उन्हें 50 किलो लेने में कोई परेशानी नहीं हुई।

श्री दादा राव की तरह ही अमराई बस्ती बागसेवनिया की श्रीमती सीमा गिरि, श्री रामस्वरूप पंडित और अन्य बस्तियों की राशन दुकान से प्याज लेने वाले लोगों ने बताया कि यह उनके लिए सरकार द्वारा दी गई राहत हैं। रसोई के लिए जरुरी 10 से 15 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज खरीदना होती थी जो नाम मात्र 2 रुपये प्रति किलो की दर पर मिली।

खाद्य आयुक्त श्री विवेक पोरवाल ने बताया कि प्रदेश में इस वर्ष राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा डेढ़ लाख किसानों से 8लाख 76 हजार मीट्रिक टन प्याज की खरीदी 8रुपये प्रति किलों की दर पर की गई। उपार्जित की गई प्याज की कुल मात्रा में से लगभग एक लाख मीट्रिक टन प्याज का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा 31 लाख परिवारों को किया गया।

ग्रामीण महिलायें बना रहीं हैं 3880 क्विंटल से अधिक अगरबत्ती हर माह

भोपाल। आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिला सदस्यों द्वारा अगरबत्ती का उत्पादन किया जा रहा है। घर बैठे किये जाने वाला यह काम उनकी अतिरिक्त आय का जरिया बन गया है। आजीविका गतिविधियों से जुड़कर महिलायें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं।

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्व-सहायता समूह सदस्यों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अन्य कार्यों के साथ-साथ अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रदेश में 1896 महिलाओं द्वारा अगरबत्ती बनाने का कार्य किया जा रहा है। पैडल एवं ऑटोमेटिक मशीनों से प्रदेश में लगभग 90 क्विंटल प्रतिदिन अगरबत्ती का उत्पादन किया जा रहा है। प्रदेश के 24 जिलों के 154 ब्लॉक में 255 अगरबत्ती यूनिट संचालित है। प्रतिमाह लगभग 3880 क्विंटल अगरबत्ती का निर्माण हो रहा है।

ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन परिवारों की महिलाओं द्वारा बनाई जा रही यह अगरबत्ती, पैकिंग, खुशबू के मामले में बहुर्राष्ट्रीय कंपनियों से पीछे नहीं है। आजीविका अगरबत्ती की बाजार में मांग बनी हुई है। बड़ी संख्या में महिलायें व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से इस कार्य से जुड़ी हुई है।

किसान को मेहनत और फसल का सही मूल्य दिलाने के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री श्री चौहान का प्याज खरीदी के लिए किसानों ने किया अभिनंदन

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की सरकार है, किसानों का हृदय से सम्मान करती है और किसानों की सभी समस्याओं के समाधान के लिये सदैव तत्पर है। इसलिये किसानों के हितों को ध्यान में रखकर ही निरंतर कड़े फैसले लिये जा रहे हैं तथा उनका बेहतर क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह बात मुख्यमंत्री निवास में विधायक श्री अनिल फिरोजिया के नेतृत्व में आये किसानों के साथ चर्चा में कही। ये किसान समर्थन मूल्य पर प्याज खरीदी की उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान का अभिनंदन करने के लिये आये थे। किसानों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान का शाल-सेहरे से अभिनंदन कर हल की काष्ठ प्रतिकृति भेंट की।

श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार का सतत प्रयास है कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा पारश्रमिक मिले, फसलों का उचित मूल्य मिले, कृषि पर बढ़ता दवाब कम हो और डिफॉल्टर किसानों की समस्याओं का समाधान भी हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसान को उनकी मेहनत और फसल का सही मूल्य दिलवाने के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया गया है कि किसानों को फसल का निर्धारित समर्थन मूल्य समय पर मिल सके। मंडी में कम मूल्य मिलने पर सरकार द्वारा शेष राशि की प्रतिपूर्ति की जाये। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों के वयस्क बच्चों को अन्य व्यवसाय की स्थापना में सहयोग के लिए सरकार की गारंटी पर 10 लाख से 2 करोड़ रूपये तक का बैंक ऋण उपलब्ध करवाने और इसमें 5 वर्ष के लिए 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दिलाने की व्यवस्था भी की जायेगी।

अपने कार्य को श्रद्धापूर्वक करें तभी सफलता संभव: श्री तिवारी,

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर में एच.डी.सी.एम. सत्र उद्घाटित

जबलपुर। कार्य को जब तक श्रद्धापूर्वक नहीं किया जायेगा तब तक उसमें सफलता मिलना मुश्किल है, चाहे प्रशिक्षण हो या हमारा कार्यक्षेत्र श्रद्धा का भाव शामिल होना आवश्यक है। ये विचार श्री पी.एस. तिवारी संयुक्त आयुक्त, सहकारिता जबलपुर संभाग ने सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, हनुमानताल जबलपुर में सहकारी प्रबंध में उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के विशेष सत्र का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किये। इस सत्र में सहकारिता विभाग के नव–पदस्थ सहकारी निरीक्षक भाग ले रहे है।

संयुक्त आयुक्त, सहकारिता ने प्रशिक्षणार्थियों से निष्ठापूर्वक प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु अपेक्षा की ओर कहा कि अपने कार्यक्षेत्र में सक्रियता पूर्वक कार्य करने के लिये प्रशिक्षण आवश्यक है। कार्यक्रम में एच.डी.सी.एम. के महत्व पर प्रकाश डालते हुए केन्द्र के प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों की ओर से श्री आलोक नायक, श्री हेमंत धाकड़ इत्यादि ने भी अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम का संचालन करते हुए व्याख्याता श्री शशिकान्त चतुर्वेदी ने केन्द्र की प्रशिक्षण गतिविधियों को विश्लेषित किया। अन्त में आभार प्रदर्शन केन्द्र के प्रशिक्षक श्री एस.के. गौतम द्वारा किया गया।

सोयाबीन कृषकों को कृषि वैज्ञानिकों की सलाह

भोपाल। सोयाबीन के कृषकों को वैज्ञानिकों द्वारा सलाह दी गई है कि जिन कृषकों ने बुवाई के तुरंत बाद अनुशंसित खरपतवार नाशको का प्रयोग नही किया हो, वे खड़ी फसल में क्लोरीम्यूरांन इथाइल (36ग्राम प्रति हेक्ट.) या इमाझेथापर (1.0 ली. प्रति हेक्ट.) या क्विजालोफाप इथाइल (1.0 ली. प्रति हेक्ट.)या फेनाक्सीफाप पी.इथाइल (0.75 ली.प्रति हेक्ट.)में से किसी एक को 500 ली पानी में मिलाकर फ्लड जेड़ या फ्लेट फेन नोजल का उपयोग कर समान रूप से खेत में छिड़काव करें। जहां पर नीला भृंग का प्रकोप हो क्विमॉलफॉस (1.5 ली.प्रति हेक्ट.)की दर से छिड़काव 500 ली. पानी के साथ करें अधिक वर्षा होने की स्थिति में खेत में किसान पानी निकासी की उचित व्यवस्था अवश्य करें।

सहकारिता में सशक्त नेतृत्व हेतु प्रशिक्षण आवश्यक

जबलपुर। सहकारिता के समुचित विकास हेतु आवश्यक है कि सहकारिता से संबंधित नेतृत्व सक्रिय व सशक्त हो और इसके लिये वनोपज सहकारी समितियों के नव निर्वाचित संचालकों को प्रशिक्षित होना जरूरी है। ये विचार सहायक आयुक्त सहकारिता श्रीमती आरती पटेल ने सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर में आयोजित वनोपज सहकारी समितियों के लिये नेतृत्व विकास पर आयोजित प्रशिक्षण शिविर के दौरान व्यक्त किये। श्रीमती पटेल ने विश्वास व्यक्त किया कि संचालकगण निष्ठापूर्वक उत्साह पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करके उसका उपयोग अपने कार्यक्षेत्र में करेंगें। राष्ट्रीय सहकारी संघ, राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केन्द्र नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य सहकारी संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में जबलपुर जिले की प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के संचालकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वागत भाषण केन्द्र के प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने दिया। व्याख्याता श्री व्ही.के. बर्वे ने प्रशिक्षण सत्र की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता श्री एस. के. चतुर्वेदी द्वारा किया गया और अंत में आभार प्रदर्शन प्रशिक्षक श्री एस. के. गौतम ने किया। आयोजन का समापन कार्यक्रम जिला वनोपज यूनियन के अध्यक्ष श्री लियाकत अली के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। श्री अली ने वनोपज समितियों की अनेक समस्याओं पर चर्चा की और प्रशिक्षण को समाधान में सहायक बताया। श्रीमती पटेल सहायक आयुक्त सहकारिता सहित केन्द्र के प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक, व्याख्याता श्री एस.के. चतुर्वेदी, श्री व्ही.के. बर्वे, प्रशिक्षक श्री एस.के. गौतम ने कार्यक्रम के दौरान वनोपज सहकारिता के विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया।

निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा करें

नर्मदा घाटी विकास मंत्री द्वारा परियोजना कार्यों की गहन समीक्षा

भोपाल। नर्मदा घाटी में सिंचाई विस्तार के लिये वर्तमान में जो निर्माणाधीन परियोजनाओं को लक्षित समयावधि में पूरा करने के लिये सघन प्रयास किये जायें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि परियोजना कमाण्ड क्षेत्र का कोई भी किसान सिंचाई लाभ से वंचित न रहे। यह बात नर्मदा घाटी विकास विभाग के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री लाल सिंह आर्य ने यहां नर्मदा भवन से परियोजना कार्यों की गहन समीक्षा के दौरान कही। श्री आर्य ने इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, मान, जोबट, पुनासा उद्वहन, अपरबेदा, लोअरगोई, रानी अवंती बाई सागर, बरगी व्यपवर्तन सहित नई स्वीकृत परियोजनाओं के निर्माण और संचालन की विस्तृत जानकारी ली।

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री रजनीश वैश ने परियोजनाओं के विभिन्न पक्षों की विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि वर्ष 2016-17 में परियोजनाओं से 5 लाख 50 हजार हेक्टेयर रकबे को जल उपलब्ध कराया गया। इसे जारी रखते हुये वर्ष 2017-18 में 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित किया जायेगा। श्री वैश ने नर्मदा मालवा गम्भीर लिंक के 65 प्रतिशत तक पूर्ण हुये कार्यों की जानकारी देते हुये सरदार सरोवर विस्थापन और पुनर्वास कार्य की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया। बैठक में प्राधिकरण के सदस्य, मुख्य अभियन्तागण तथा पुनर्वास से संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन

नौगांव (छतरपुर)। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस 01 जुलाई 2017 पर सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रातः 9.00 बजे केन्द्र के प्राचार्य श्री सुधीर कुमार जैन, द्वारा प्रांगण में सहकारी ध्वजारोहण किया व झंडा वंदन पश्चात केन्द्र अधिकारी/कर्मचारियों व प्रशिक्षार्थियों ने सहकारी गीत का गायन किया। प्राचार्य श्री जैन ने उपस्थित जन समुदाय के समक्ष भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली से प्राप्त सहकारी संदेश का वाचन किया व सहकारी आंदोलन के विकास के लिये समर्पित भाव से कार्य करने पर जोर दिया।

श्री जैन ने अपने संबोधन में कहा कि सहकारी आन्दोलन को मजबूत करने में, विस्तार करने में सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण योगदान है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण का कार्य करने वाले संस्थानों को आधुनिक सुविधाओं से तकनीकि संसाधनों से सुसज्जित किया जाये। देश की विभिन्न सहकारी संस्थाओं के सदस्यों को आपस में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश व एक देश से दूसरे देश अध्ययन भ्रमण के लिये भेजा जाये ताकि सहकारिता में नवाचार शीघ्रता व सरलता से व सदस्यों द्वारा किया जा सके।

श्री जैन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 95 वें तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 23 वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस का आयोजन पूरे विश्व में किया जा रहा है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस का विचार बिंदु है सहकारी आन्दोलन से कोई वंचित न रहे। इस अवसर पर आज हम सब शपथ लें कि हम अपने प्रदेश व देश में सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ करने में निस्वार्थ भाव से कार्य करेंगें साथ ही सहकारी संस्थाओं में अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर उन्हें जागरूक करेंगे।

खरीफ सीजन में अब तक 76 लाख 37 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में हुई बोनी

भोपाल। मध्यप्रदेश में खरीफ सीजन में इस वर्ष अब तक 76 लाख 37 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी की जा चुकी है। प्रदेश में इस वर्ष 132 लाख 46 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की बोनी का कार्यक्रम तय किया गया है। पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश से बोनी में तेजी आई है। कृषि विभाग ने किसानों को इस वक्त दलहन फसलों में उड़द, मूंग और तिलहनी फसल में तिल की तेजी से बोनी करने की सलाह दी है।

इस वर्ष प्रदेश में खरीफ सीजन में धान 6 लाख 43 हजार हेक्टेयर में बोया गया है। धान की बोनी के लिये 23 लाख 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्र का कार्यक्रम तय किया गया है। ज्वार 79 हजार हेक्टेयर क्षेत्र और मक्का 10 लाख 43 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बोया गया है। प्रदेश में अब तक 36 लाख 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बोनी की गई है। इस वर्ष प्रदेश में 53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बोनी किये जाने का कार्यक्रम तय किया गया है। प्रदेश में इस सीजन में अब तक 248.3 मिमी बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में 14 जुलाई तक सामान्य औसत वर्षा 249.5 मिमी होती है।

डेढ़ लाख किसानों से तीन लाख मी. टन दलहन फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी

किसानों को प्रचलित दरों से रूपये पाँच सौ करोड़ से अधिक का भुगतान

भोपाल। प्रदेश में किसानों से ग्रीष्मकालीन मूंग, उड़द एवं अरहर की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। ग्रीष्मकालीन उड़द एवं मूंग की खरीदी 10 जून और तुअर की खरीदी 13 जून से प्रारंभ की गई है।

राज्य शासन द्वारा 10 जून से अभी तक 1,53,649 किसानों से 3,06,915 मी. टन दलहन फसलों का समर्थन मूल्य पर क्रय किया गया, जिसकी कुल लागत रूपये 1,522 करोड़ है। राज्य सरकार द्वारा इन किसानों को रूपये 503.17 करोड़ का मण्डी में प्रचलित दरों से अधिक भुगतान किया गया।

मूंग की प्रचलित मण्डी दर रूपये 3300 प्रति क्विंटल है जबकि समर्थन मूल्य रूपये 5,225 प्रति क्विंटल है। अभी तक 92,468 कृषकों से 1,93,480 मी. टन मूंग समर्थन मूल्य पर क्रय की गई है, जिसकी कुल कीमत रूपये 1010.93 करोड़ है। इसी प्रकार, समर्थन मूल्य पर मूंग क्रय कर कृषकों को रूपये 371.50 करोड़ अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायी गई है।

मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना अंतर्गत उड़द की खरीदी रूपये 5000 प्रति क्विंटल की दर से 13,132 किसानों से 25,570 मी. टन क्रय की गई, जिसका मूल्य रूपये 127.50 करोड़ है, जबकि प्रचलित मण्डी दर रूपये 4100 प्रति क्विंटल रही। किसानों के शासन द्वारा उड़द खरीदी द्वारा प्रचलित दर से रूपये 22.95 करोड़ की राशि अतिरिक्त रूप से भुगतान की गई।

प्रदेश में अरहर के विपुल उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए रूपये 5,050 प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर 68,085 मी. टन अरहर (रूपये 305.51 करोड़ मूल्य) का उपार्जन 24,399 कृषकों से किया गया। प्रचलित मण्डी दर रूपये 3700 प्रति क्विंटल की तुलना में कृषकों को रूपये 91.91 करोड़ा का ज्यादा लाभ प्रदाय कराया गया है।

मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना अंतर्गत रूपये 3,950 प्रति क्विंटल की दर से 19,780 मी. टन मसूर 8,050 किसानों से क्रय की गई। इसकी कुल क्रय कीमत रूपये 78.21 करोड़ है। मण्डी की प्रचलित दर रूपये 3,100 प्रति क्विंटल की तुलना में रूपये 16.81 करोड़ की अतिरिक्त राशि किसानों को उपलब्ध कराई गई।

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-
डी.सी.ए. मात्र 8100/-
न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए. स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)
प्रवेश प्रारंभ
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित
सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध
प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल
(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)
ई-8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड-462 039
फोन.-0755 2725518, 2726160 फेक्स-0755 2726160
Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

शहरीकरण का बेहतर प्रबंधन संभव : मुख्यमंत्री श्री चौहान

मप्र ने की शहरी प्रबंधन, नियोजन में सराहनीय प्रगति - ईशर जज आहलूवालिया

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शहरीकरण की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता लेकिन बेहतर प्रबंधन संभव है। बेहतर प्रबंधन से शहर स्वर्ग बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि गांव तेजी से शहर की ओर बढ़ रहे हैं। इससे शहरों के लिये चुनौतियाँ भी पैदा हो रही हैं। इसलिये बेहतर शहरी प्रबंधन और नियोजन पर ध्यान देना जरूरी हो गया है।

श्री चौहान यहाँ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ईशर जज आहलूवालिया की किताब 'हमारे शहरों का रूपांतरण' का विमोचन कर रहे थे। इस किताब का प्रकाशन मंजुल प्रकाशन द्वारा किया गया है। इस अवसर पर पूर्व में कार्यरत योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह आहलुवालिया एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

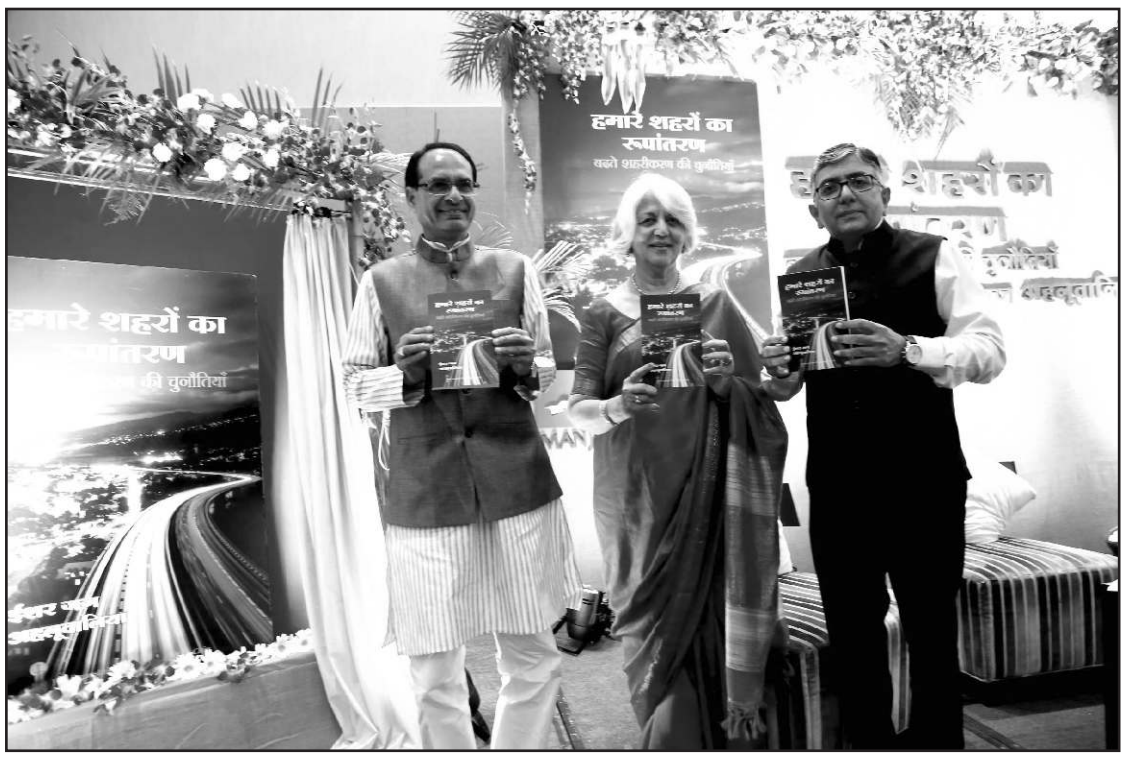

श्री चौहान ने कहा कि हाल के सफाई सर्वेक्षण में सौ शहरों में 22 मध्यप्रदेश के हैं। इनमें भी इंदौर प्रथम और भोपाल दूसरे स्थान पर है। प्रदेश के सात शहर स्मार्ट शहर की सूची में शामिल हैं। श्री चौहान ने हिन्दी में इस किताब के प्रकाशन का महत्व बताते हुये कहा कि यह शहरी निकायों, प्रबंधन से जुड़े प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं के लिये मार्गदर्शी साबित होगी। उन्होंने कहा कि सभी शहरी निकायों को यह किताब उपलब्ध करायी जायेगी।

किताब की लेखिका ईशर जज आहलूवालिया ने शहरी प्रबंधन और नियोजन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश द्वारा की गई प्रगति की सराहना करते हुये कहा कि मध्यप्रदेश स्मार्ट सिटी के लिये उपलब्ध फण्ड का बेहतर उपयोग कर रहा है। उन्होंने इंदौर में निजी और सार्वजनिक भागीदारी से शहर बस सेवा की परियोजना पर चर्चा करते हुये कहा कि भोपाल और इंदौर में शहरी यातायात में अनूठा काम हुआ है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिबद्धता से शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करते हुये बेहतर प्रक्रिया और व्यवस्थायें स्थापित की हैं उनकी प्रेरणादायी कहानियाँ किताब में शामिल की गई हैं।

सरकारी अस्पतालों में है निःशुल्क डायलिसिस सुविधा

भोपाल। प्रदेश के 51 जिला अस्पतालों में 26 जनवरी, 2016 से किडनी मरीजों के लिये निःशुल्क डायलिसिस सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। अन्य शासकीय अस्पताल में सुविधा का विस्तार करने के लिये विभाग को 25 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाई गई है। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ जिला स्तर पर निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। केन्द्र शासन ने भी मध्यप्रदेश को रोल मॉडल मानते हुए देश के हर जिले में डायलिसिस इकाइयों की स्थापना की घोषणा की है।

मरीज को समान्यतः सप्ताह में दो बार डायलिसिस की आवश्यकता होती है। जिसके लिए रोगी को माह में लगभग 20-25 हजार रुपये तक खर्च करना पड़ता था। शासकीय अस्पताल में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले मरीजों को यह सुविधा पूर्णतः निःशुल्क और एपीएल मरीजों को मात्र 500 रुपये प्रति सत्र की दर से उपलब्ध करवाई जा रही है। यह सुविधा प्रारंभ होने से पहले किडनी रोग पीड़ित मरीज जो बड़े शहर या रा%य के बाहर जाकर इलाज करवाते थे, उन्हें अब यह सुविधा उनके जिले में ही मिलने लगी है।

किडनी मरीजों के लिए वरदान

नरसिंहपुर जिले के 32 वर्षीय करेली निवासी श्री शाकिर मोहम्मद ने बताया कि वे पहले जबलपुर के निजी अस्पताल में डायलिसिस करा रहे थे। जहाँ उन्हें हर बार 2,500 रुपये का खर्चा आता था। इसी तरह ग्राम मगरदा निवासी 40 वर्षीय श्रीमती विमला बाई ने बताया कि वे मार्च 2016से लगातार डायलिसिस पर हैं और उन्हें 96बार सुविधा का लाभ मिल चुका है। यदि शासकीय सहायता न मिलती तो श्रीमती विमला बाई इस इलाज का खर्च नहीं उठा पातीं। उनके परिजनों ने कहा कि यह सुविधा किडनी मरीजों के लिये वरदान सिद्ध हो रही है।

महिला आयोग ने बिखरे परिवारों को जोड़ा

भोपाल। राज्य महिला आयोग में हुई सुनवाई में तीन दम्पत्तियों ने पिछले गिले-शिकवे भुलाकर एक बार फिर से साथ-साथ दाम्पत्य जीवन बिताने का निर्णय लिया। वहीं एक दम्पत्ति ने 15 दिन का समय माँगा। श्रीमती लता वानखेड़े की अध्यक्षता में हुई आयोग की संयुक्त बैंच में 30 प्रकरण की सुनवाई की गयी। अधिकतर मामले पारिवारिक विवाद और दहेज प्रताड़ना के थे। सुनवाई में आयोग की सदस्य श्रीमती गंगा उइके, श्रीमती अंजू सिंह बघेल, श्रीमती सूर्या चौहान, श्रीमती प्रमिला वाजपेयी और श्रीमती संध्या सुमन राय भी मौजूद थीं।

राज्य महिला आयोग द्वारा भोपाल में दूसरे चरण की सुनवाई शुरू की गयी है। पहले चरण में महिला आयोग ने प्रदेश के सभी 51 जिलों में संयुक्त बैंच के माध्यम से 7000 से अधिक प्रकरण की सुनवाई की है।

किसानों से समर्थन मूल्य पर एक अरब रुपये से अधिक की प्याज खरीदी गई

भोपाल। देवास जिले में प्रशासन की व्यापक व्यवस्थाओं के बीच पिछले सप्ताह तक ग्राम भौंरासा के कृषक श्री मनोज जोशी और श्री जगदीश माली, ग्राम बेड़ामऊ के श्री श्रवण सेंधवा, ग्राम भटौनी के श्री जीतेन्द्र सिंह, हाटपिपल्या के श्री पर्वत सिंह की तरह 20 हजार 199 किसानों ने समर्थन मूल्य पर खरीदी केन्द्रों पर 12 लाख 71 क्विंटल प्याज बेची। खरीदी केन्द्रों पर पुख्ता व्यवस्था के फलस्वरूप इन किसानों को एक अरब रुपये से भी अधिक का भुगतान किया गया।

कृषक मनोज पिता चंद्रशेखर जोशी निवासी भौंरासा ने 5 बीघा क्षेत्र में प्याज बोई थी। प्याज के भाव नहीं मिलने से परेशान थे। इसी बीच प्रदेश सरकार ने फैसला लिया कि सभी किसानों से 8रुपए प्रतिकिलो के हिसाब से प्याज खरीदी जाएगी। मनोज जोशी 18 जून, 26 जून एवं 30 जून 2017 को मंडी में पहुँचे और 650 कट्टे प्याज बेची। प्याज बेचने के लिए उन्हें टोकन दिए गए थे। इसी गाँव के किसान जगदीश माली ने दो बीघा जमीन में प्याज लगाई थी, जिसमें करीब 250 कट्टे प्याज पैदा हुई। अगर सरकार समर्थन मूल्य पर प्याज की फसल खरीदी नहीं करती तो इनकी लागत भी नहीं निकलती। जगदीश माली ने बताया कि उन्हें प्याज उपार्जन में अच्छे दामों में प्याज बेचने से फायदा हुआ।

ग्राम बेडामऊ के कृषक श्रवण सेंधव के पास 3 बीघा जमीन है। इन्होंने एक बीघा में प्रशांत नस्ल की प्याज लगाई। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष एक बीघा में ही 150 कट्टे प्याज का बम्पर उत्पादन हुआ। मंडी में 3 रुपए प्रति किलो प्याज ही जा रही थी। क्या थोक भाव, और क्या खेरची, सभी में लागत और मेहनत निकालना मुश्किल था। इन्हें अखबारों से पता चला कि सरकार 8रुपए प्रतिकिलो के भाव से प्याज खरीदेगी और खरीदी केंद्र भी स्थापित करेगी तो मन में उम्मीद जागी। प्याज की गाड़ी लेकर जब हाटपीपल्या खरीदी केंद्र पहुँचे तो देखी लंबी-लंबी लाइन। प्रशासन की टोकन व्यवस्था देखी तो काम आसान हो गया। श्रवण सेधव ने भी टोकन लिया और वहीं मंडी समिति में कम मूल्य पर उपलब्ध भोजन किया। भोजन पानी की व्यवस्था काफी ठीक थी। श्रवण ने बताया कि वहां जगह कम पड़ने पर खरीदी बंद कर दी गई तो हमने देवास मंडी में आकर प्याज बेची। टोकन की वजह से अफरा-तफरी नहीं हुई।

हाटपीपल्या तहसील के ग्राम भटौनी के किसान जितेंद्र सिंह पिता मनोहर सिंह के पास 30 बीघा रकबा जमीन हैं। इनके 2 बीघा में प्रशांत नस्ल की 150 कट्टे प्याज की पैदावार हुई। पानी कम था, इससे पैदावार अन्य कृषकों के मुकाबले थोड़ी कम हुई थी, पर पर्याप्त थी। खरीदी केंद्रों में 8 रुपए किलो का भाव देखकर इन्होंने सीधे मंडी की ओर रूख कर लिया। वहाँ उनकी प्याज उचित मूल्य पर खरीदी गई। खरीदी केंद्रों पर टोकन व्यवस्था अच्छी थी। साथ ही भोजन भी सर्व सुलभ था। हाटपीपल्या के ही कृषक पर्वत सिंह के पास 5 बीघा जमीन है, जिसमें से उन्होंने 2 बीघा जमीन में प्याज लगाई थी। इनका परिवार बरसों ऐसी ही परम्परागत खेती करता आ रहा है।

मुख्यमंत्री डैश बौर्ड पर लोक सेवा प्रदाय कानून की प्रतिदिन होगी समीक्षा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कलेक्टर-कमिश्नर की वीडियो कांफ्रेंसिंग में दिये निर्देश

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्वच्छ प्रशासन का संदेश जनता तक पहुँचे। सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कमिश्नर और कलेक्टरों से कहा है कि राजस्व प्रशासन उनका बुनियादी काम है। इसे चुस्त-दुरुस्त बनाने को सर्वो%च प्राथमिकता दें। जनता को लोक सेवा प्रदाय कानून की सेवायें समय-सीमा में मिलें। इसमें विलम्ब होने पर जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई की जाये। इसमें शिथिलता मिलने पर नियंत्रक अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित कर कार्रवाई की जायेगी। श्री चौहान कमिश्नर-कलेक्टरों की वीडियो कांफ्रेंसिंग को संबोधित कर रहे थे। कांफ्रेंसिंग में राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लोक सेवा प्रदाय कानून के प्रकरणों के निराकरण की दैनिक स्थिति पोर्टल पर उपलब्ध होगी, ऐसी व्यवस्था की गई है। वे स्वयं पोर्टल की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों को भी उनके कार्य क्षेत्र में प्रकरणों के निराकरण की विभाग, अधिकारी और सेवावार जानकारी उपलब्ध होगी। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे व्यवस्थायें चॉक-चौबंद कर लें मुख्यमंत्री समीक्षा में यदि गड़बड़ी मिली तो संबंधित जिला कलेक्टर, संभागायुक्त की प्रतिष्ठा धूमिल होगी। श्री चौहान ने निर्देश दिये कि लोक सेवा प्रदाय कानून में विभिन्न विभाग को 53 ऑनलाइन सेवाओं को सी.एम. डैश बोर्ड से संलग्न करवाया जाये। ऑफलाइन 58 सेवाओं को भी शीघ्र ऑनलाइन करें। अधिसूचित सेवाओं की जानकारी आमजन तक पहुँचाने के प्रयासों को युद्धस्तर पर किया जाये। कार्य से संबद्ध अधिकारी-कर्मचारियों का भी गहन प्रशिक्षण करवाया जाये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राजस्व विभाग सीधे जनता से जुड़ा है। इसलिये जरूरी है कि विभाग की सेवायें, तत्परता और सहजता से आमजन को मिलें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्राथमिकता तय कर कार्य करें। हर जिला राजस्व मामलों की समाधान व्यवस्था को लंबित प्रकरणों से मुक्त बनायें। नये प्रकरण निर्धारित समय-सीमा में निराकृत हो, लंबित प्रकरण एक भी नहीं है, इसका दावा जिला करें। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी का बुनियादी काम राजस्व सेवायें है। वे निरंतर भ्रमण और निरीक्षण कर, व्यवस्थाओं की निगरानी करें। लंबित प्रकरणों की संख्या शून्य करने के लिये अभियान चलाने, पखवाड़ा मनाने और मुहिम चलाने आदि कार्यों की योजना भी बनाई जाये।

कांफ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण महाभियान के पौधों के रख-रखाव की निगरानी करवाने, बाढ़ नियंत्रण और राहत-बचाव संबंधी सावधानियों, प्रयासों के प्रति सचेत रहने के निर्देश दिये।

मीटर रीडर्स के लिये कार्ड सिस्टम लागू करने पर विचार

ऊर्जा विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक में श्री पारस जैन

भोपाल। ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन ने कहा है कि बिजली मीटर की रीडिंग लेने वाले कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये कार्ड सिस्टम लागू करने पर विचार किया जा रहा है। यह पहल बिजली उपभोक्ताओं की मीटर रीडर्स के संबंध में प्राप्त शिकायतों को ध्यान में रखते हुए की गई है। अनेक उपभोक्ताओं की शिकायत रहती है कि मीटर की बिना रीडिंग लिये बिजली के बिल दिये जाते हैं। श्री पारस जैन विधानसभा भवन स्थित समिति कक्ष में ऊर्जा विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में समिति के सदस्य, विधायक सर्वश्री सूबेदार सिंह रजौधा, बलवीर सिंह डण्डौतिया, हर्ष यादव और सुश्री ऊषा ठाकुर उपस्थित थे।

श्री जैन ने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत लाईन में खराबी आने पर उसे तत्काल सुधारा जाये। विद्युत की उपलब्धता एवं प्रवाह में व्यवधान नहीं होना चाहिये। बिगड़े हुए ट्रांसफार्मर आम दिनों में तीन दिन में तथा बरसात के दौरान अधिकतम सात दिन में बदले जाना चाहिये। ऊर्जा मंत्री ने समय-सीमा का ध्यान नहीं रखने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित लाईनमेन पदस्थ किये जायें। गत माह हुई बिजली पंचायत में जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनमें निराकृत होने से शेष रह गई शिकायतों का त्वरित निराकरण करवाया जाये। जन-प्रतिनिधियों द्वारा जो शिकायतें की जाती हैं, उनकी ओर भी अधिकारी ध्यान दें। विद्युत के क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे।

बैठक में सदस्यों ने विद्युत व्यवस्था के सुधार के संबंध में सुझाव दिये। इस अवसर पर मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी के प्रबंध संचालक श्री संजय शुक्ल, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के प्रबंध संचालक श्री एम. सेलवेन्द्रम, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के प्रबंध संचालक श्री आकाश त्रिपाठी, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के प्रबंध संचालक श्री मुकेश चंद्र गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कृषको को सामयिक सलाह

भोपाल। किसानों के द्वारा अपने खेत में रबी एवं खरीफ फसलें की जाती है। कृषकों द्वारा एक ही फसल एक ही समय में अधिक क्षेत्र में लगाई जाती है जिससे बाजार में वह फसल एक साथ आ जाती है । जिस कारण विपणन में समस्या आती है । बाजार भाव भी नीचे स्तर पर पहुंच जाता है । साथ ही भण्डार व्यवस्था कम होने से उत्पाद सुरक्षित रखने में दिक्कतें आती हैं, इस कारण किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है ।उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने किसानों से अपील की है कि मौसम की अनुकूलता एवं मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखकर विभिन्न फसलों की बोनी करें, ताकि बाजार में फसलों की आवक एवं दरें पर्याप्त रूप से स्थिर रखी जा सके एवं किसानों को आर्थिक नुकसान न उठाते हुए अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके।

देश में मॉडल बना राज्य महिला आयोग

भोपाल। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबद्ध संस्था आइनी द्वारा कोलकता में हुए दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पर हुए परिसंवाद में मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें अन्य राज्यों में लागू करने का सुझाव दिया गया है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती लता वानखेड़े ने आयोग द्वारा महिला सशक्तीकरण, महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के प्रयास, जमीनी स्तर पर महिलाओं की सहायता के लिये आयोग द्वारा जिलों में बनाये गये आयोग सखी और सहयोगी समितियों की जानकारी परिसंवाद में दी थी।

परिसंवाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पूर्व जस्टिस सुश्री जयमाला मुखर्जी, कार्यक्रम संयोजक श्री हेनरी, देश के विभिन्न राज्यों के महिला आयोग, अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग, मानव अधिकार आयोग, बाल संरक्षण आयोग के सदस्यों ने भाग लिया। मध्यप्रदेश से आयोग की अध्यक्ष श्रीमती लता वानखेड़े सदस्यगण श्रीमती गंगा उईके, श्रीमती प्रमिला वाजपेयी, श्रीमती सूर्या चौहान, श्रीमती संध्या राय, श्रीमती अंजू सिंह बघेल मौजूद थी।

निर्माण विभाग महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करें : मुख्यमंत्री

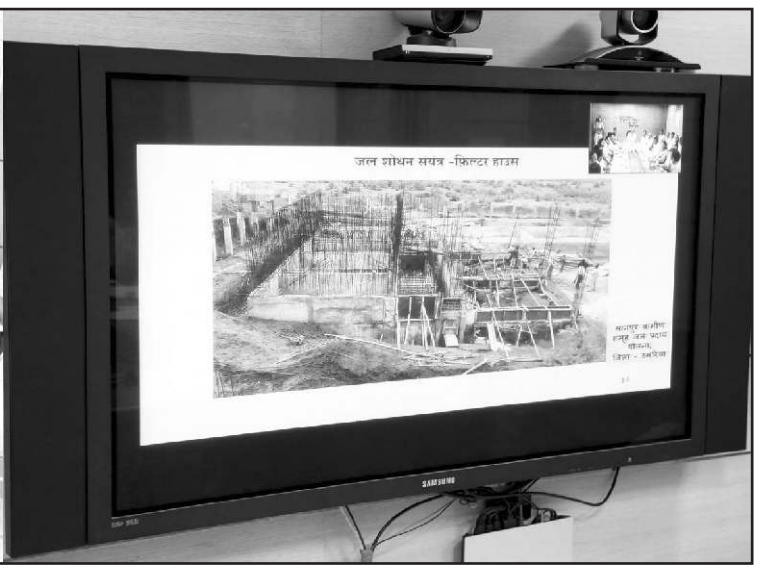

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्माण विभागों को निर्देशित किया है कि कार्यों की गुणवत्ता, निर्माण अवधि आदि के महत्वांकाक्षी लक्ष्य निर्धारित कर कार्य किये जायें। श्री चौहान मंत्रालय में प्रगति ऑनलाइन के दौरान निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। ऑनलाइन समीक्षा में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रकाशन **समझ झरोखा** का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति, कार्य की पूर्णता और गुणवत्ता के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने आदिम जाति कल्याण विभाग के निर्माणाधीन कन्या शिक्षा परिसरों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रदेश के 28जिलों में 65 परिसरों का निर्माण किया जाना है। कुल 52 स्थलों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गये हैं। मुख्यमंत्री ने उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता की जानकारी मिलने पर संबंधित जिलों के कलेक्टरों और परियोजना क्रियान्वयन इकाई से सीधा संवाद किया। उन्होंने अधिकारियों को एक सप्ताह में उपयुक्त भूमि चयन का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में सीधी जिले की ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना मझोली, उमरिया जिले की ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना मानपुर, कन्या शिक्षा परिसर, बैतूल-खंडारा-आमला-बोरदेहि-बांसखापा-नागदेव मंदिर रोड, खमरपानी-सावरनी-लोधी खेड़ा- रेमंड चौक रोड, निवारी-सेंद्री रोड, बेनजीर पैलेस का हेरिटेज होटल में रूपांतरण, पूर्व क्षेत्र में फीडर सेपरेशन, रीवा की अमृत योजना अंतर्गत सीवरेज परियोजना और जबलपुर स्टेट कैंसर इंस्टिट्यूट परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कार्य को समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिये।

केन्द्रीय स्मार्ट विलेज परियोजना में प्रदेश के 60 गांव चयनित

पर्यावरण मंत्री श्री आर्य ने किया राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ

भोपाल।जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से किसानों और फसल उत्पादन को बचाने के लिये केन्द्र शासन द्वारा आरंभ क्लाइमेट स्मार्ट विलेज परियोजना में प्रदेश के 3 जिलों के 60 गाँव का पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में चयन किया गया है। पर्यावरण मंत्री श्री अन्तर सिंह आर्य ने आज एप्को में परियोजना की राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के गाँव के चयन के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का प्रदेश की जनता की ओर से आभार प्रगट किया। विधायक श्री नारायण प्रसाद त्रिपाठी एप्को के कार्यपालन अधिकारी श्री अनुपम राजन भी मौजूद थे। परियोजना में चयनित सीहोर, राजगढ़ और सतना जिले के 20-20 गाँवों के लिये केन्द्र द्वारा 24 करोड़ 87 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

पर्यावरण मंत्री श्री आर्य ने कार्यशाला में संबंधित जिलों के भाग ले रहे जनपद अध्यक्ष, कार्यपालन अधिकारी, पंचायतों के सरपंच और सचिव को संबोधित करते हुए कहा कि वे प्रदेश में ही नहीं देश में भी अपने-अपने गाँव को मॉडल क्लाइमेट स्मार्ट विलेज के रूप में स्थापित करें। पर्यावरण बचाने के लिये पौध-रोपण बहुत जरूरी है।

विधायक श्री त्रिपाठी ने किसानों का आव्हान करते हुए कहा कि वे सोलर पम्प का उपयोग करें। देश में मध्यप्रदेश के स्मार्ट विलेज को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। खाद, बीज, बिजली, पानी मिलने से किसान मजबूत हो जायेगा। उन्होंने बताया कि वे शीघ्र ही अपने क्षेत्र मैहर में 50 हजार पौध रोपण करवा रहे हैं।

कार्यपालन अधिकारी श्री राजन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से सर्वाधिक प्रभावित किसान ही है। असंतुलित वर्षा और हानिकारक गैस के उत्सर्जन से फसल, उत्पादन, उत्पादकता और खाद्यान्न प्रजाति प्रभावित हो रही है। पृथ्वी की सतह के एक डिग्री तापमान बढ़ने के साथ ही फसल उत्पादन में 10 प्रतिशत की कमी आ जाती है। दक्षिण अफ्रीका में तापमान बढ़ने से मुख्य फसल मक्का उत्पादन में 30 प्रतिशत की कमी आई है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये सही खाद, बीज, ऊर्जा प्रबंधन आदि पर काम करने की जरूरत है।

केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एनएएफसीसी के तहत क्लाइमेट स्मार्ट विलेज देश की पहली परियोजना है जो पूर्णत: केन्द्रीय अनुदान आधारित है।

क्लाइमेट स्मार्ट विलेज मिट्टी और जल के संरक्षण, फसल की सूखा सहनशील किस्मों की खेती, कृषि वानिकी द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने तथा मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि की नवीन पद्धतियों पर आधारित परियोजना है। कार्यशाला में नार्बाड, मौसम और कृषि विभाग के विषय-विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं।

प्रदेश में हुई 2 लाख 9 हजार 982 मीट्रिक टन मूंग की खरीदी

भोपाल। प्रदेश में किसानों से ग्रीष्मकालीन मूंग, उड़द और अरहर की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। समर्थन मूल्य पर 26जुलाई तक मूंग की 2 लाख 9 हजार 982 मीट्रिक टन खरीदी की जा चुकी है। किसानों से उड़द 32 हजार 226मीट्रिक टन खरीदी गयी। किसानों को उनकी उपज का भुगतान भी नियत समय में किया गया है।

प्रदेश में अब तक की स्थिति में खरीफ फसलों की बोवाई संतोषजनक है और फसल बोवाई का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा। आज की स्थिति में 93 लाख 86 हजार हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बोवाई हो चुकी है। पिछले वर्ष आज की स्थिति में यह क्षेत्रफल 96 लाख 28हजार हेक्टेयर था। प्रदेश में खरीफ की बोवनी के लिये 130 लाख 48हजार हेक्टेयर का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित है। आज की स्थिति में सोयाबीन की बोवाई पिछले वर्ष के 49 लाख 70 हजार हेक्टेयर की तुलना में 40 लाख 12 हजार हेक्टेयर में हो चुकी है।

दस हजार पटवारियों की भर्ती होगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया फसल गिरदावरी मोबाइल एप का शुभारंभ

भोपाल। किसानों के हित के लिये इस वर्ष से फसल गिरदावरी संबंधी जानकारी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से संग्रहीत की जायेगी। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पटवारियों को उनके मोबाइल पर ही ग्राम के समस्त भूमि स्वामियों के सभी खसरों की जानकारी प्राप्त हो जायेगी। लगायी गयी फसल की जानकारी ग्राम से ही भरी जा सकेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने समन्वय भवन में मोबाइल एप का शुभारंभ किया।

श्री चौहान ने कहा कि राजस्व अमले की कमी पूरी करने के लिये जल्दी ही 10 हजार पटवारियों, 550 तलसीलदारों और 940 नायब तहसीलदारों की भर्ती की जायेगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दे दिये गये हैं। उन्होंने राजस्व विभाग प्रमुख को पटवारियों की विभागीय पदोन्नति के संबंध में भी विचार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिये युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने पटवारियों को सूचना प्रोद्योगिकी का उपयोग करने के लिये टेब खरीदने के लिये उनके खाते में आवश्यक राशि देने की घोषणा की। श्री चौहान ने कहा कि सरकार पूरी तरह से लोगों के प्रति जवाबदेह है। उन्होंने कहा कि बोनी के समय के आँकडों का शुद्ध रेकार्ड उपलब्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिये हर संभव कदम उठाये जा रहे हैं। किसानों को समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य के अंतर के आधार पर आदर्श दर से भुगतान करने का नवाचारी प्रयोग भी किया जायेगा।

मोबाइल एप से होने वाले लाभों की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि राजस्व विभाग का यह क्रांतिकारी कदम भविष्य में बदलाव लायेगा। पारंपरिक बस्ते से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने एप संचालन के लिये एनआईसी का उपयोग करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लोगों को राजस्व विभाग और इसके अमले से बहुत अपेक्षाएँ हैं।

क्या है फसल गिरदावरी

फसल गिरदावरी प्रतिवर्ष की जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह वर्ष में दो बार खरीफ और रबी सीजन की बुवाई के बाद की जाती है। इसे भू-अभिलेखों में दर्ज किया जाता है। यह कृषि सांख्यिकी एकत्रित करने की प्रक्रिया है। इसके आधार पर फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन संबंधी अनुमान की जानकारी तैयार की जाती है।

कृषि वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होता है। प्रथम खरीफ की फसलों तथा द्वितीय रबी की फसलों के आधार पर चालू वर्ष के खसरे में बोए गए क्षेत्रफल की फसल गिरदावरी के आधार पर दर्ज की जाती है। गिरदावरी जितनी सही और समय पर होगी, कृषि सांख्यिकी पूरी तरह से विश्वसनीय रहेगी।

क्यों जरूरी है गिरदावरी

फसल गिरदावरी के आधार पर ही खरीफ और रबी फसलों के बोए गए रकबे के आँकड़े प्राप्त होते हैं। उस आधार पर प्रमुख फसलों के उत्पादन व उत्पादकता अनुमान तथा राज्य एवं देश की कृषि दर निर्धारित की जाती है।

फसल गिरदावरी कार्य से ही फसल पूर्वानुमान लगाया जाता है, जिससे फसल गिरदावरी को राजस्व खसरे के रकबे के आधार पर सांख्यिकी कार्य के लिये जानकारी शासन को प्रेषित की जाती है। यह जानकारी कई मामलों जैसे फसल बीमा, प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई, बैंक ऋण, योजनाओं के लाभ लेने आदि में महत्वपूर्ण होती है।

मोबाईल एप्लीकेशन

इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पटवारियों को उनके मोबाइल पर ही ग्राम के समस्त भूमि स्वामियों के सभी खसरों की जानकारी प्राप्त हो जायेगी। जैसे ही भरी गयी जानकारी अपलोड की जायेगी, कृषक को उससे संबंधित खसरों में फसल गिरदावरी के अंतर्गत कौन सी जानकारी दर्ज की गयी है, यह सूचना एस.एम.एस. के माध्यम से भेजी जायेगी। इसमें एक पासकोड भी होगा।

प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पांडे ने मोबाइल एप के बारे में जानकरी दी। इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी.मीणा, प्रमुख सचिव कृषि डॉ.राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी उपस्थित थे। आयुक्त भू-अभिलेख श्री एन.के. अग्रवाल ने आभार माना।

मनरेगा के पंचायत भवनों से मिलने लगी लोक सुविधाएँ

भोपाल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम (मनरेगा) से पंचायत मुख्यालयों पर बनाये गये पंचायत भवनों से आमजन को लोक सुविधाएँ आसानी से मुहैया होने लगी हैं। अब ग्रामीणों को शासन की महती योजनाओं का त्वरित लाभ मिलने लगा है। पंचायत भवन में उचित बैठक व्यवस्था और विभिन्न योजनाओं की कम्प्यूटीकृत जानकारी प्राप्त होने लगी है। अब ग्राम पंचायत कार्यालय जाकर ग्रामीण द्वारा मनरेगा में काम की मांग करना, योजनाओं के लाभ लेने हेतु आवेदन करना और ग्रामसभा की कार्यवाही में भाग लेना और अधिक सुविधाजनक हो गया है। भारत की दो तिहाई से अधिक आबादी आज भी ग्रामीण इलाकों में निवास करती है। शासन ने इन ग्रामीणों को आधारभूत सुविधाएँ मुहैया कराने और गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनायी गई है, जिनका क्रियान्वयन मूलरूप से ग्राम पंचायत स्तर से ही किया जाता है। मध्यप्रदेश में मनरेगा से अब तक 1600 से अधिक ग्राम पंचायत भवन निर्मित किये जा चुके हैं। चार हजार पंचायत भवन निर्माणधीन है, जिन्हें शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा। पंचायत भवनों के निर्माण से ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो रही है और ग्रामीणजन को इसका लाभ मिल रहा है।

मनरेगा से बनाये गये इन पंचायत भवन निर्माण में अधिकतम दस लाख रूपये मनरेगा से तथा शेष राशि पंच परमेश्वर योजना, विधायक/सांसद निधि से जुटाई गई है। क्लस्टर मुख्यालय की ग्राम पंचायत भवन की लागत 14.15 लाख रूपये तथा अन्य ग्राम पंचायत भवन निर्माण की लागत 12.85 लाख रूपये रखी गई है। पंचायत भवन में मीटिंग हॉल, सरपंच कक्ष, सचिव कक्ष, दस्तावेज संधारण हेतु कक्ष, शौचालय आदि का निर्माण किया गया है।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा सांध्य प्रकाश लि.'सांध्यप्रकाश भवन' मालवीय नगर, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।